free sale quota for 9 years and 66% in the 10th year.

(b) The Incentive Scheme has been formulated for new and expansion projects established at high capital cost, with a view to enable them to repay the term loans taken from the financial institutions. There is no provision in the scheme to provide incentives for existing loss-making sugar units of any sector.

Management of PDS by State Government

3141. SHRI RAMDAS AGARWAL :

Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether Government have decided to handover the responsibility of procurement, management and distribution of foodgrains to the States themselves;

(b) whether the State Government would be provided with additional funds/subsidies for management through Public Distribution System; if not, the reasons therefor; and

(c) if so, the actual allocation made in the current year's fund and proposed in 1993-94 budget, State-wise ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) to (c) No proposal is under consideration of the Central Government to change the existing policy of procurement and distribution of foodgrains. Foodgrains are procured by Food Corporation of India in cooperation with the States and their agencies. This foodgrain is thereafter issued ex-FCI godowns at subsidised rates to the States/Union Territories and thereafter its distribution to consumers is the responsibility of the States/Union Territories. The Central Government provides increasing food subsidy every year. In 1992-93 (RE) the provision of food subsidy is Rs. 2800 crores, a provision of Rs. 3000 crores has been made in 1993-94.

उत्तर प्रदेश में स्वीकृत चीनी की मिलें

3142. **श्री राम नरेश यादव** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश के लिए चीनी की कितनी मिलें मंजूर की गई हैं और इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ख) इनमें से कितने स्थानों पर मिलों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है; और

(ग) शेष मिलों को स्थापित करने संबंधी कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 1992 से अब तक कोई आशय पत्र प्रदान नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Procurement of Wheat

3143. SHRI IQBAL SINGH :
SHRI SURESH PACHOURI :

Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what difficulties were faced by Government in the procurement of wheat during the last three years; and

(b) whether Government have prepared any action plan to improve food economy ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) The procurement of wheat for the central pool under price support was 110.65 lakh tonnes during the 1990-91 rabi marketing season; 77.52 lakh tonnes during the 1991-92 rabi marketing season; and has been 63.80 lakh tonnes till 12th March, 1993 during the current 1992-93 rabi marketing season.

The main reason for decline in procurement of wheat during the 1991-92 and 1992-93 rabi marketing seasons can be stated as higher open market prices, large scale purchases by the traders; less mandi arrivals; and possible holding back of stocks by farmers in anticipation of higher prices later in the year, etc.

(b) Various aspects of food economy remain under constant review by Government and appropriate action is taken wherever and whenever called for.

मध्य प्रदेश में चीनी का उत्पादन

3144. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में चीनी के कारखानों में कुल कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन हुआ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रही चीनी के कारखानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

चीनी वर्ष (सितम्बर-अक्तूबर)	उत्पादन (लाख टन)
1989-90	0.72
1990-1991	1.03
1991-92 (अनंतिम)	1.28

(ख) सरकार चीनी फैक्टियों को होने वाले लाभ/घाटे का रिकार्ड नहीं रखती है । तथापि, सरकार चीनी फैक्ट्रियों को पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए आसान शर्तों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराती है । गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में चीनी उपक्रमों को गन्ना विकास/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से मंजूर की गई ऋण सहायता निम्न प्रकार है :—

वर्ष (अप्रैल–मार्च)	मंजूर की गई राशि (रु. लाख में)
1989-90	362.77
1990-91	435.00
1991-92	—

मध्य प्रदेश में पंजीकृत चीनी मिलें

3145. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पंजीकृत चीनी मिलों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इनमें अलग-अलग क्वालिटी की चीनी का कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में 8 संस्थापित चीनी मिलें हैं ।

1991-92 मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान इन चीनी फैक्टियों का गुणवत्तावार चीनी का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

ग्रेड	उत्पादन (टन)
एल-30	280
एम-30	52,836
एम-29	72
एस-30	74,348
एस-29	676
मानक से नीचे	599
अनग्रेडिड	372
कुल	1,29,183

खाद्यान्नों की सप्लाई

3146. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** :
श्री अनन्त राम जायसवाल :
श्री दिग्विजय सिंह :
श्री राम नरेश यादव :
श्री रवीन्द्र कुमार यादव 'रवि' :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों के